# विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तारी पर रोक

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर को राहत देते हुए जवाहर नगर थाने में उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. में गिरफ्तार किए जाने पर रोक लगा दी।**
- **यह केस यू.आई.टी. कोटा के उप सचिव की रिपोर्ट पर यू.आई.टी. की सहायक अभियंता ज्योति रानी वर्मा व निजी सचिव कौशल किशोर ने दर्ज करवाया था।**
- **दिलावर के वकील का कहना है कि, यह केस राजनैतिक द्वेष के कारण दर्ज करवाया गया था, क्योंकि दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी थी।**

जयपुर, 16 मार्च (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर को राहत देते हुए उनके खिलाफ जवाहर नगर थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष से चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता दिलावर को भी निर्देश दिए हैं कि वह प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करे।

दिलावर की याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गत 23 फरवरी को जवाहर नगर थाने में झूठा मामला दर्ज कराया गया है। याचिकाकर्ता आमजन का निर्वाचित प्रतिनिधि है। विपक्ष के तौर पर याचिकाकर्ता को सरकार की कड़ी आलोचना करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्व में पांच अन्य मामले में दर्ज कराए गए थे। राज्य सरकार उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा कर जनप्रतिनिधि की आवाज को बंद कराना चाहती है।

गौर फरमाने योग्य है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच झगड़ा व शत्रुता अपने चरम पर थी और सचिन पायलट गुट के कई विधायकों को नोटिस जारी हुए थे। इसके साथ ही विद्रोही विधायकों पर देशद्रोह के मामले भी हाईकोर्ट में दायर हुए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अशोक गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत साबित करने के लिये पर्याप्त विधायक नही हैं।

तब मदन दिलावर ने बसपा के सभी विधायकों के कांग्रेस पार्टी में मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि बसपा के पार्टी अध्यक्ष ने इन विधायकों को कांग्रेस पार्टी में मिलने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि हाईकोर्ट के इस मामले में अपना फैसला सुनाने या "स्टे" लगाने से पूर्व ही सचिन पायलट गुट जयपुर लौट आया था।

दिलावर के खिलाफ दर्ज मामला यह है, यूआईटी कोटा के उप सचिव की रिपोर्ट लेकर न्यास की सहायक अभियंता ज्योति रानी वर्मा व निजी सचिव कौशल किशोर ने गत 23 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मंगलवार दोपहर विधायक मदन दिलावर सहित करीब डेढ़ दर्जन लोग न्यास कार्यालय आए और सचिव से मिलने की जिद करने लगे। मामले में दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार जब विधायक मदन दिलावर को बताया गया कि सचिव राजकार्य से जयपुर गए हैं। इस पर वे आग बबूला हो गए और सचिव के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से धरना देकर बैठ गए। विधायक कर्मचारियों पर दबाव बनाकर कार्य करने को मजबूर कर रहे थे और उन्होंने अपशब्द भी कहे। वहीं कार्यालय समय पूरा होने के बाद निजी सचिव कौशल किशोर को बाहर निकाल कर रात को न्यास सचिव के चैम्बर में कब्जा कर लिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 353 व धारा 448 के तहत मामला दर्ज किया था।

## जापान के प्रधानमंत्री 19 मार्च को भारत आयेंगे

नई दिल्ली, 16 मार्च (वार्ता)। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 19 मार्च को भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगें। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ वर्तमान समय में रूस-यूक्रेन विवाद पर भी दोनों प्रधानमंत्री अपने विचार साझा कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बातचीत संभव है।

- **जापान के प्रधानमंत्री का यह दौरा 2019 में ही प्रस्तावित था, किन्हीं कारणों से दौरा टल गया था, लेकिन अब जापान ने इस मामले में आगे बढ़कर पहल की है।**

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच वर्ष 2019 में मुलाकात होने वाली थी लेकिन भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण मुलाकात को स्थगित कर दिया गया था।

# अवैध बजरी से भरा ट्रेलर पलटा, तीन मरे

- **तेज रफ्तार से जोधपुर से नागौर जा रहे ट्रेलर के पलटने से साथ चल रही बाईक पर सवार तीन लोगों की बजरी व ट्रेलर के नीचे दबने से मौत हो गई।**
- **तीनों मृतकों की पहचान के प्रयास चल रहे हैं, समझा जाता है कि तीनों मजदूर थे।**

जोधपुर, 16 मार्च (कासं)। जोधपुर शहर में अवैध रूप से बजरी का खनन लगातार जारी है। बजरी माफिया पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं कि अक्सर निर्दोष लोग उनकी चपेट में आ जाते हैं। बुधवार की सुबह भी ऐसा ही हुआ। जोधपुर से नागौर की तरफ जा रहा अवैध बजरी से भरा एक ट्रेलर पलटी खाने के बाद बाइक सवार तीन मजदूरों पर गिर गया। बजरी और ट्रेलर के नीचे दबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोपहर तक मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे थे। संभावना है कि मजदूर आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। ट्रेलर पलटने की सूचना पर सूरसागर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई की। बजरी को हटाने पर तीन श्रमिक नीचे दबे मिले। उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया। मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

सूरसागर थानाधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि सुबह छह से सात बजे के बीच में इस दुर्घटना की जानकारी मिली थी। बजरी से भरा ट्रेलर तेज गति से नागौर की तरफ जा रहा था। कालीबेरी रोड पर पहुंचने पर वह अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। इससे पास में एक बाइक पर चल रहे तीन श्रमिक दब गए। पुलिस ने वहां पहुंच कर बजरी को हटवाने के साथ ट्रेलर को सीधा करवाया तो तीन श्रमिक दबे मिले, अस्पताल भेजने पर डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि शहर में सुबह बजरी माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वे अवैध रूप से बजरी का लदान भारी वाहनों में करने के साथ पुलिस से बचने के चक्कर में तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। पहले भी ऐसे हादसों में कई लोगों की जानें जा चुकी है। बासनी, सांगरिया, बनाड़ और महामंदिर इलाके में कई मौतें हो चुकी हैं।

## पूर्व सैनिकों की पेंशन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सशस्त्र सेनाओं के जवानों के लिये "एक पद, एक पेंशन" की 2015 की नीति को यथावत रखते हुये, सरकार को निर्देश दिये है कि पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई, 2019 से बकाया चल रही पेंशन 3 माह के अन्दर दे दी जाये तथा हर पाँच वर्ष बाद इसे संशोधित किया जाये।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ तथा सूर्यकांत से मिलकर बनी बैंच ने बुधवार को अपने फैसले में आदेश दिये कि 7 नवम्बर, 2015 के कम्यूनिकेशन में कहा गया है कि पेंशन का पुनर्निधारण हर पाँच साल पर होगा तथा यह 1 जुलाई, 2019 से बकाया है। केन्द्र ने कहा कि केन्द्र इस कवायद को पूरा करेगा तथा सशस्त्र सेनाओं के सभी पात्र पेंशनरों को तीन महीने में एरियर्स का भुगतान करेगा।

- **सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये कि, 1 जुलाई 2019 से पूर्व सैनिकों की बकाया पेंशन को तीन माह में दे दें तथा हर पांच साल पेंशन की राशि का पुनः निर्धारण करें।**

पेंशन की दरों में भविष्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने पर, इनकी पेंशन के स्वतः संशोधन के संबंध में, वादी-पूर्व सैनिकों से संबंधित इस विवाद पर, बैंच की ओर से बोलते हुये न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा, "इन बिन्दुओं को संदर्भ के लिहाज से एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट हैं कि पुराने पेंशनरों को पेंशन की दरें बिना किसी प्रशासनिक अडंगे के मिलेंगी। "स्वतः पहुँचें" शब्दावली के अर्थ को, लाभों की गणना के लिये किसी भी समयावधि के संदर्भ से जुड़े वादे के रूप में संकुचित या सीमित न कर दिया जाये।"

# भगवंत मान ने ली पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ

## शहीद भगत सिंह के गांव में हुआ शपथ ग्रहण समारोह

खटकड़ कलाँ (शहीद भगत सिंह नगर), 16 मार्च (वार्ता)। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने बुधवार को यहां पंजाब के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

शहीदेआज़म भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकड़कलां में 40 एकड़ में बनाये गये पंडाल में लाखों लोगों की मौजूदगी में मान को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बसंती रंग में सराबोर माहौल में मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया।

इस मौके पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तथा दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित शख्सियतों ने शिरकत की। इस समारोह में सियासी हस्तियों को नहीं बुलाया गया लेकिन कला तथा रंगमंच की दुनिया की हस्तियों को न्यौता दिया गया। ज्यादातर कलाकार मान के करीबी रहे।

प्रसिद्ध लोक गायक गुरदास मान, कांग्रेस के सांसद एवं कलाकार मोहम्मद सदीक और अनेक जाने-माने लोग उनके शपथ समारोह में पहुंचे।

समारोह में 'आप' के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक और पंजाब मामलों के प्रभारी जरनैल सिंह, विधायक और पंजाब मामलों के सह-प्रभारी राघव चड्ढा के अलावा 'आप' के कई नवनिर्वाचित विधायक, वरिष्ठ नेता, पंजाब के पार्टी कार्यकर्ता और वॉलंटियर उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शपथ समारोह पर जनता के खून-पसीने के करोड़ों रुपये फूंके गये।

चुघ ने बयान में कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कोई सादगीपूर्ण किया कार्यक्रम नहीं था बल्कि यह किसी राजा-महाराजा की ताज़पोशी की तरह किया गया।

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि 150 एकड़ की फसल को बर्बाद कर दिया गया, जिसके लिए अब मान उन किसानों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यह बताएं कि 150 एकड़ की फसल कितने लोगों का पेट भर सकती थी, उस नुकसान की भरपाई कौन और कैसे करेगा।

चुघ ने कहा कि आप को प्रचंड बहुमत मिला है और उसे 'विघटनकारी' भूमिका नहीं निभाना चाहिए क्योंकि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

## कश्मीर में बुधवार को मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गये

श्रीनगर, 16 मार्च (वार्ता)। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों को मार गिराया।

अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि मारे गए आतंकवादी पिछले सप्ताह एक सरपंच समीर अहमद भट्ट की हत्या में शामिल थे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में आतंकवादियों छिपे होने की सूचना मिलने के बाद, सुरक्षा बलों ने करीब आधी रात के आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया और इस मुठभेड़ में आतंकवादियों के मंसूबों के नाकामयाब कर उनको मार गिराया।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा, हमें मंगलवार रात को एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया कि नौगाम में तीन से चार आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने इलाके की घेराबंदी करके और इस क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। करीब रात दो बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए।

# शशि थरूर भी जी-23 में शामिल हुये

## गुलाम नबी आज़ाद के घर पर मीटिंग हुई जिसमें शशि थरूर सहित कई नेता शामिल हुये

- **शशि थरूर के कांग्रेस के बागी नेताओं के ग्रुप जी-23 में शामिल होने से कांग्रेस हाई कमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।**

नई दिल्ली, 16 मार्च। पांच राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पार्टी के अंदर असंतुष्ट खेमा लगातार बैठक के जरिए पार्टी हाई कमान के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहा है। बुधवार को एक बार फिर जी-23 सदस्यों ने गुलाम नबी आजाद के घर बैठक की। इस बैठक में शशि थरूर भी शामिल हुए हैं। थरूर के जी-23 ग्रुप में शामिल होने से हाई कमान की मुश्किल बढ़ सकती है।

बुधवार शाम को डिनर मीटिंग के लिए जी-23 सदस्यों ने गुलाम नबी आजाद के घर दौड़ लगाई। यह बैठक इसलिए भी ज्यादा अहम माना जा रही है क्योंकि रविवार को कांग्रेस कार्यसमिति ने पांच घंटे की मैराथन बैठक की थी। आजाद के घर बैठक में शामिल होने वालों में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपिंदर हुड्डा, अखिलेश प्रसाद सिंह, पृथ्वीराज चव्हाण, राज बब्बर, पीजे कुरियन और मणिशंकर अय्यर शामिल थे। इससे पहले जी-23 सदस्यों ने चुनाव परिणामों के दिन भी बैठक की थी और एक सुर में पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी।

शशि थरूर, जो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका जी-23 बैठक में हिस्सा लेना निसंदेह बड़ी बात है। इससे पहले आज ही शशि थरूर ने ट्वीट करके अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने लिखा, "मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब सोच रहा हूं आगे बढ़ूं।"

बताया जा रहा है कि जी-23 सदस्यों की बैठक पहले कपिल सिब्बल के घर होनी थी। लेकिन बीते रोज सिब्बल का सब की कांग्रेस वाले बयान के बाद बैठक की जगह गुलाम नबी आजाद के घर को चुना गया। जी-23 सदस्यों ने सिब्बल के बजाय आजाद के घर बैठक करके पार्टी हाई कमान को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो सिब्बल के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बताते चलें कि सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह आखिरी सांस तक घर की कांग्रेस से सब की कांग्रेस के लिए लड़ते रहेंगे।

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की पुष्टि की थी कि सोनिया गांधी ने रविवार को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नेताओं को संबोधित करते हुए अपने और अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की पेशकश की थी। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसे सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था।

## गहलोत के...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

को उनके सामने रखें, जिन पर आज मीटिंग में चर्चा हुई है। मुद्दे की बात तो यह है कि क्या गांधी भाई-बहिन उस बात को सुनने के लिये तैयार भी हैं, जो उनसे कही जा रही है।

आज़ाद की डिनर मीटिंग में कपिल सिब्बल, आनन्द शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चव्हाण, भूपिन्दर सिंह हूडा, परनीत कौर, मणिशंकर अय्यर, बघेला, संदीप दीक्षित सहित अन्य कई नेता शामिल थे।

आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है तथा ज्यादा संकट की अपेक्षा इस कारण है कि गांधी परिवार साफ दिखाई दे रही इबारत को पढ़ने से ही इंकार न कर दे।

## राष्ट्रपति के चुनाव ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

लिये प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य भी वोट देते हैं।

ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के पास देश में आधे विधायक भी नहीं हैं, इसलिये अपने पसंदीदा प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनवाना उसके लिये मुश्किल होगा।

भाजपा के पास राज्यों के आधे विधायक भी न होने की स्थिति में, भाजपा के अपने पसंदीदा उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित करा पाना बहुत मुश्किल होगा।

उन्हें अब भी ऐसी उम्मीद है कि वे सभी विपक्षी दलों में इस प्रकार की आपसी समझ-बूझ बना लेंगी कि वे सब मिलकर अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुन सकें।

ऐसी कोशिश वे पहले भी कर चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के चुनाव के समय भी इसी प्रकार की गोल-मोल बात कही थी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिये उस समय भी उनके दिमाग में कुछ अन्य नाम थे।

लेकिन देश के अति चतुर राजनेताओं में से एक नेता ने उन्हें अपनी चतुराई से मात दे दी थी। मुलायम सिंह यादव की चतुराई के आगे ममता की यह योजना धरी रह गई थी कि वे राष्ट्रपति पद के लिये अपनी पसंद के प्रत्याशी को ला सकें।

मुलायम अंतिम क्षणों में एकाएक बदल गये थे और ममता बनर्जी देखती रह गई थीं।

# कर्नाटक में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बंद की घोषणा की

## सभी मुस्लिम संगठन हिज़ाब पर प्रतिबंध के खिलाफ एक सुर में लामबंद हुये

- **मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने बुधवार को घोषणा की कि, वे गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे। हमारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से इस मामले में बात हुई है।**
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई थी।**

बेंगलुरु, 16 मार्च (वार्ता)। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब को लेकर सुनाये गये फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने गुरुवार को 'कर्नाटक बंद' का आह्वान किया है।

गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और विद्यालय के यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र-छात्राएं आपत्ति नहीं कर सकते। न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार है।

अदालत के फैसले से खफा मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कल कर्नाटक बंद का आव्हान किया है। मुस्लिम नेताओं ने स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है। कल के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है।

मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने बुधवार को घोषणा की कि, वह कल मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक नेता मंगलवार को हिजाब पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। बैठक अमीर ए शरीयत के आवास पर हुई। बैठक में सलीम अहमद, जमीर अहमद खान, यूटी खादर, एनए हैरिस, नजीर अहमद, रहमान खान, खानिज फातिमा और अन्य ने भाग लिया था।

अदालत के फैसले के बाद छात्रों द्वारा दिए गए बयान पर मौलवियों ने आपत्ति जताई है। उनका रवैया ठीक नहीं है, उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। वर्दी को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। हमें भी उच्चतम न्यायालय में जाने की इजाजत है। कांग्रेस नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बात हो चुकी है। आमिर ए शरीयत ने कल सभी नेताओं को सलाह दी कि वे समाज में अनावश्यक भ्रम पैदा न करें।

## आर्बिट्रेशन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मध्यस्थता की उन प्रक्रियाओं को फिर से शुरु करने की अनुमति दे दी, जो एमेज़ॉन ने सिंगापुर में फ्यूचर ग्रुप के विवाद में की थीं। ज्ञातव्य है कि फ्यूचर ग्रुप ने मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के साथ 24,713 करोड़ रू. के असैट सेल डील की पेशकश की थी।

अदालत ने यह अनुमति इसलिये दी कि दोनों पक्ष, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित समझौता-वार्ता के जरिये, किसी सैटलमैंट की स्थिति तक नहीं पहुँचे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिविजन बैंच ने जनवरी में, अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के समक्ष, एमेज़ॉन तथा फ्यूचर ग्रुप के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया पर "स्टे" लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एमेज़ॉन तथा फ्यूचर ग्रुप के बीच के इस केस की सुनवाई करते हुये, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा "सिंगापुर ऑबिट्रेशन ट्रिब्यूनल सैन्टर (एस.आई.ए.सी.) पर दिये गये "स्टे" को हटा दिया।

- **एमेज़ॉन व फ्यूचर ग्रुप को आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त दी सुप्रीम कोर्ट ने।**

शीर्ष अदालत ने फ्यूचर ग्रुप तथा एमेज़ॉन से पूछा कि क्या उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया के पुनः शुरु करने में कोई परेशानी है। अगर कोई परेशानी या समस्या नहीं है तो यह अदालत मध्यस्थता की कार्यवाही पुनः शुरु किये जाने का आदेश दे देगा। दोनों ही पक्षों ने पक्के तौर पर कह दिया कि उन्हें ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं हैं।

## राजस्थान में...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

रमना की अध्यक्षता वाली बैंच के समक्ष रखते हुये कहा कि "जल्दी सुनवाई इसलिये जरूरी है कि बहुत सी लड़कियों को कॉलेज जाना हैं।" उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि इस प्रकरण की सुनवाई अगले सप्ताह के पहले दिन ही कर ली जाये।

हेगड़े ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जो भारतीय संविधान के मूल ढ़ाँचे का एक हिस्सा है, का उल्लंघन करते हुये, उच्च न्यायालय का यह फैसला मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम बालिकाओं/महिलाओं के बीच अनुचित भेदभाव पैदा कर रहा हैं।

## वियतनाम में करोना मामलों का रिकॉर्ड बना

हनोई, 16 मार्च (वार्ता/शिन्हुआ)। वियतनाम में कोविड-19 का दैनिक प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में बुधवार को यहां 1,80,558 नए मामले दर्ज हुए जो मंगलवार के मुकाबले 5,078 अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। देश भर में 62 इलाकों से 1,80,552 स्थानीय मामले तथा छह मामले विदेशों से सामने आये हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई में बुधवार को 26,220 मामले सामने आए तथा मध्य नघे प्रांत में 10,797 मामले और उत्तरी विन्ह फुक प्रांत में 8,875 मामले दर्ज हुए। इसी अवधि में थान होआ और नघे एन के दो संघीय इलाकों में 86,982 मामलों की पुष्टि हुई। जानकारी के अनुसार, देश में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 68,20,458 हो गयी है।

# 'सोशल मीडिया के मार्फत सुनियोजित ढंग से देश में नफरत फैलाई जा रही है'

## सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि, छद्म न्यूज़ प्रचारक फेसबुक के मार्फत विषाक्त ईकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं

- **कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में राजनीतिक विचारों एवं सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने के सुनियोजित प्रयासों पर गहरी चिंता जतायी और सरकार से आग्रह किया कि वह इस प्रकार के खतरे से हमारे लोकतंत्र की रक्षा करे।**

नई दिल्ली, 16 मार्च (वार्ता)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में राजनीतिक विचारों एवं सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने के सुनियोजित प्रयासों पर आज गहरी चिंता जतायी और सरकार से आग्रह किया कि वह इस प्रकार के खतरे से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की रक्षा करे।

सोनिया गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि हमारे लोकतंत्र को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से खतरा बढ़ रहा है। फेसबुक एवं ट्वीटर जैसी वैश्विक कंपनियों का नेताओं, पार्टियों एवं उनके छद्म कार्यकर्ताओं द्वारा खास प्रकार के राजनीतिक विचारों को स्थापित करने के लिए प्रयोग बढ़ रहा है। लोगों के संज्ञान में यह बार-बार आ रहा है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं करा रहीं हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा कि फेसबुक के खुद के घृणास्पद अभिव्यक्ति संबंधी नियम सत्ता पक्ष के राजनीतिज्ञों के पक्ष में धूमिल हो रहे हैं। हाल ही में अल ज़जीरा और रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने दर्शाया है कि छद्म प्रचारकों द्वारा समाचार माध्यमों के नाम से फेसबुक पर एक विषाक्त ईकोसिस्टम हमारे देश में चुनावी कानूनों को दरकिनार करके और फेसबुक के नियमों के विरुद्ध जाकर सरकार के खिलाफ आवाजों का दमन किया जा रहा है। सत्ताधारियों के साथ मिल कर फेसबुक द्वारा जिस आक्रामकता से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि युवा एवं प्रौढ़ मस्तिष्क में भावनात्मक रूप से भ्रामक सूचनाओं से घृणा भरी जा रही है और फेसबुक जैसी छद्म प्रचार कंपनियां इस बात को जानतीं हैं और वे उससे मुनाफा कमा रहीं हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़े कारोबारी घरानों, सत्ताधारियों एवं फेसबुक जैसी वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियों के बीच इस प्रकार की सांठ-गांठ बढ़ रही है।

श्रीमती गांधी ने कहा, मैं सरकार से आग्रह करतीं हूं कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के सुनियोजित हस्तक्षेप एवं प्रभाव को समाप्त करे।

## कांग्रेस ने हार की जांच के लिए पदाधिकारी भेजे

नई दिल्ली, 16 मार्च (वार्ता)। कांग्रेस ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों की जांच के लिए पांच महासचिव नियुक्त किए हैं, जो हार के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन नामों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने श्रीमती रजनी पाटिल को गोवा, जयराम रमेश को मणिपुर, अजय माकन को पंजाब, अविनाश पांडे को उत्तराखंड और जितेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश भेजा है और कहा है कि वहां विधायक का चुनाव लड़ने वाली पार्टी के उम्मीदवारों के साथ ही अन्य नेताओं से बातचीत करें और हार के कारणों के साथ ही चुनाव के बाद की स्थिति का जायजा लें।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908